उत्तर प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते बैंक

1964. **श्री ईश दत्त यादव:**

श्री गोपाल सिंह जी० सीलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते बैंक खोले गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1993 की स्थिति के अनुसार ऐसे क्षेत्रों के जिला-वार नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या इन बैंकों द्वारा कोई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार चालू तथा अगले वर्ष के दौरान देश के और अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे और अधिक बैंक खोलने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) गुजरात और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कार्य कर रहीं चल-शाखाओं को विवरण में दर्शाया गया है (नीचे देखिए) । चल शाखाएं, संबंधित बैंक की किसी न किसी एक विद्यमान पूर्ण शाखा से सम्बद्ध होती हैं जो मूल शाखा के रूप में कार्य करती हैं । चल शाखाएं सामान्यत: वे सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करती हैं जो संबंधित मूल शाखाओं पर उपलब्ध कराई जाती हैं ।

(ङ) और (च) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चालू शाखा विस्तार नीति (1990-95) के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में (चल शाखाओं सहित) अतिरिक्त शाखायें खोलने का कार्य, संबंधित बैंकों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है । तदनुसार, बैंकों को ग्रामीण ऋणों की सेवा क्षेत्र योजना को प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए जांच कर आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त/चल शाखाएं खोलने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने होते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक, आवेदक बैंक के सेवा क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त ग्रामीण शाखाओं/अतिरिक्त चल शाखाओं को चलाने के प्रस्तावों पर, जिन्हें संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदित कर राज्य सरकारों के माध्यम से भेजा जाना होता है । सामान्यत: सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है । अब तक, भारतीय रिजर्व बैंक को वर्तमान नीति के अन्तर्गत चल शाखा खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

गुजरात और उ०प्र०में कार्यरत मोबाइल शाखाएं

गुजरात

क्र०सं०	जिला	मोबाइल शाखाओं द्वारा कवर गांवों के नाम
1.	बड़ौदा	सामा, मांजोली, पिपरिया, आसोज
2.	पंचमहल	सेहा, दारियाना, गोराडा
3.	कच्छ	लेखापार, नागलपार, चंदिया, शिमोगा
4.	मेहसाणा	टिंटोदान, बिहार, पउसम, समउा, अजोल, रिदरौल

5. भावनगर . .	नभेबादा, बुडैल, कावडी, साखन्सका, तांसा, पंचपिपला, राजपारा, घनघोली, सिदसर, भुम्भेली संपारा, कोलियाक
6. भुज . .	मनकुवा, कोडकी, फोतदी, समराला, मिर्जापुर, सरली, मेघपार, फुंदनपुर और सूरजपुर
7. खंद्रा . .	अलिंद्रा, अखदोल, बंधनी, चुनैल, घोरा, लिंगदा, मनघोली मिराल, पतगौल, पनसौरा, पिपलाग, गनतौल
8. जूनागढ़ . .	अदवाना, भगवादर, बलेज, शाखारला, भरवादा, चिकसा, दिगम, हाथियानि, खम्भोदर, खिस्त्री, केन्द्रखेड़ा, कुच्छादि, गंजीवाना, नागका, रतेदी, तिकड़ा, टुकड़ा (गोसा)
9. दादरा नागर हवेली (संघ राज्यक्षेत्र)	दापड़ा, दुधानी, किलवानी, मनदौनी, मोटा रन्धे
उत्तर प्रदेश	
1. हरिद्वार . .	शिवलिक नगर, बहादुराबाद, ग्राम चिल्ला
2. मेरठ . .	मिलिटरी हस्पताल, 271 इन्फे० आर्ट्री ब्रिगेड 510, आर्मि-बेस वर्कशाप 416 इंजिनियरिंग ब्रिगेड 71, मोद रागु, 67 एफ डी रेजिमेंट
3. देहरादून . .	कौलागढ़, नहरु नगर, हारेवाला
4. मिर्जापुर . .	भुइली, भाइपुर, खारवा, मन्नौर
5. जालौन . .	बांगरा
6. सुल्तानपुर . .	हनुमान गंज, कंता गंज, बारांसे, बन्दउ कलां
7. वाराणसी . .	मोहन सराय, मियामतावाद
8. इलाहाबाद . .	धरवारी, कौदीहर

Sectoral Loans by World Bank

1965. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) Whether the World Bank has agreed to provide a sectoral adjustment loan to India;

(b) if so, what are the details of the loan;

(c) what are the details of the sectors for which this loan would be available: and

(d) in what manner Government propose to utilise this loan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) to (d) Yes, Sir. The World Bank has approved an External Sector and Investment Liberalisation Programme Loan on June 24, 1993 for an amount of US$ 300 million. This is a fast disbursing loan provided to India as a measure of balance of payment support for the reform measures in the areas of external trade and investment liberalisation already taken by us. The amount of the loan will be utilised to finance the essential imports for the country such as POL, etc.